THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेसविज्ञप्ति

ब्यूरो के प्रमुख 2 फरवरी**, 2021**

ICSI केंद्रीय बजट 2021 का स्वागत करता है

सीएस नागेंद्र डी राव, अध्यक्ष, आईसीएसआई

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI), 1 फरवरी, 2021 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा अनावरण किए गए बजट 2021 का स्वागत करता है।

बजट 2021 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए परिव्यय में 137% की महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। कोविद -19 वैक्सीन विकास और टीकाकरण पर रु 35000 करोड़ के साथ स्वास्थ्य सेवा पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय एक बहुत आवश्यक कदम है।

केवल पेंशन और ब्याज आय रखने वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने, और व्यक्तिगत कर दाताओं के लिए फेसलेस विवाद समाधान समिति की स्थापना के साथटैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल फेसलेस करने, वरिष्ठ और छोटे कर दाताओं को अनुपालन में प्रदान की गई सरलता के लिए, संस्थान सराहना करता है।

मंत्रालय की एक विस्तारित शाखा के रूप में, संस्थान NRI के लिए दोहरे कराधान को हटाने के लिए नए नियमों के बारे में की गई पहल और अन्य उपायों के बीच कर निर्धारण की समय अवधि में कमी की सराहना करता है। स्टार्ट-अप को एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए अपने कर अवकाश में विस्तार मिलेगा। लाभांश आय की अग्रिम देयता लाभांश के भुगतान की घोषणा के बाद उत्पन्न होगी।

बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) इंडेक्स में उन्नति को बढ़ाते हुए, भुगतान किए गए पूंजी और टर्नओवर पर प्रतिबंध के बिना एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) को अनुमति देने के लिए एवं विभिन्न प्रतिभूति बाजार नियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक बाजार कोड प्रस्ताव किया गया है। ओपीसी को किसी भी समय किसी भी प्रकार की कंपनी में बदलने की अनुमति दी जाएगी, एक भारतीय नागरिक को

ओपीसी स्थापित करने के लिए निवास की सीमा 182 दिनों से घटाकर 120 दिन कर दी गई है और गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी इसमें अनुमति दी जाएगी।

ई-स्क्रूटनी, ई-एडजुडिकेशन, ई-परामर्श और अनुपालन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल के साथ MCA21 संस्करण 3.0 बनाने के लिए एवं डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली एक योजना का प्रस्ताव करने से लेकर, इस बार के पेपरलेस बजट ने शासन और व्यवसायों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया।

बजट पर अपने विचार हुए,आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस नागेंद्र डी राव ने कहा, "कोविद -19 महामारी के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर बजट 2021 के सुधार उपायों में सरकार ने अर्थव्यवस्था के छह स्तंभों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जिसमे स्वास्थ्य, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, रीइन्विगेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड आरएंडडी, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का विचार संरेखित हैं।

प्रीति कौशिक बनर्जी
निदेशक
कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले
दूरभाष: 011-4534 1022
ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu